The ACHIEVERS IAS ACADEMY

ACHIEVERS
IAS ACADEMY
PATNA

Summary of the Hindu

16 February 2023

Medium English

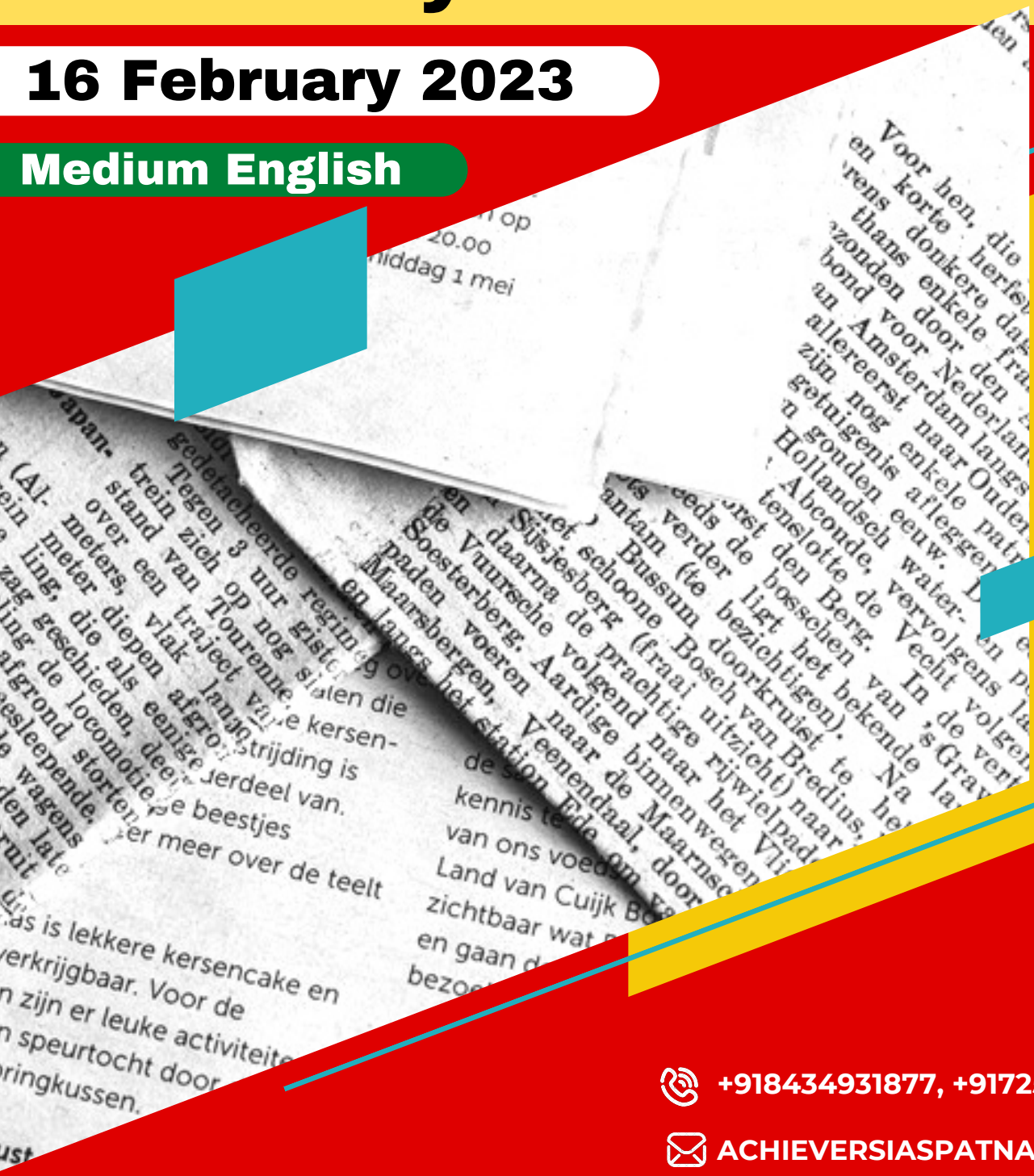

2023
CURRENT AFFAIRS

+918434931877, +917250667974

ACHIEVERSIASPATNA@GMAIL.COM

NEW PATLIPUTRA COLONY ROAD NO. 4A, NEAR TENNIS COURT, PATNA-13

WWW.ACHIEVERSIASPATNA.CO.IN

हिन्दू 16-02-23 राष्ट्रीय

भारत-चीन सीमा पर भारत की नजर:-

कैबिनेट ने सुरक्षा पर आईटीबीपी की 7 बटालियन कैबिनेट समिति को अरुणाचल प्रदेश सीमा पर आईटीबीपी के 7 नए पदों को मंजूरी दी। आईटीबीपी में 9,400 जवानों की सुरक्षा कर इसे अंजाम दिया जाएगा। जीवंत ग्राम कार्यक्रम के तहत सीमावर्ती क्षेत्रों में पलायन रोकने के लिए 4800 करोड़ रुपये आवंटित।

वर्तमान में अरुणाचल प्रदेश में 3,488 किमी एलएसी के साथ आईटीबीपी की 176 चौकियां हैं, 47 नई सीमा चौकियां और 12 स्टेजिंग कैंप निर्माणाधीन हैं।

अरुणाचल प्रदेश में ITBP के एक सेक्टर मुख्यालय की भी घोषणा की गई है।

आईटीबीपी - भारत-तिब्बत सीमा पुलिस आईटीबीपी भारत चीन सीमा (एलएसी) की रक्षा करती है। यह अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और लद्दाख की सीमाओं की रक्षा करता है। वर्तमान में आईटीबीपी के 88,000 कर्मचारी हैं, जो कैबिनेट के फैसले के बाद टेलीफोन पर बढ़कर 97,000 हो जाएंगे।

उत्तराखंड ने जोशीमठ राहत योजना

- **अब तक :-**

जनवरी, 2023 में उत्तराखंड के जोशीमठ शहर में कई इमारतों, सड़कों में दरारें आने की सूचना मिली है, जिसके बाद एनडीआरएफ ने शहर को साफ किया और एक विध्वंस अभियान शुरू किया जिसमें कई इमारतों, वाणिज्यिक परिसरों को ध्वस्त कर दिया गया। विस्थापितों के पुनर्वास को लेकर चिंता और गुस्सा था।

हाल का घटनाक्रम- राज्य सरकार लागत और स्थिति के आधार पर प्रभावित परिवारों के स्थायी पुनर्वास के लिए 3 विकल्प दे रही है।

विकल्प-1 - सरकार प्रभावितों को मुआवजा देगी।

विकल्प-2 – प्रभावित परिवार या व्यक्ति सरकार से जमीन और क्षतिग्रस्त भवन के मुआवजे की मांग कर सकता है।

विकल्प 3 - कोई व्यक्ति या परिवार अपनी भूमि भवन के सापेक्ष निर्मित आवासीय भवन की मांग कर सकता है।

सरकार ने परिवारों के रोजगार के लिए भी योजना बनाई है

एचएएल भारत में एमक्यू-9बी ड्रोन इंजन के लिए रखरखाव और ओवरहाल समर्थन प्रदान करेगा।

हिंदुस्तान एक्रोनॉटिक्स लिमिटेड और जनरल एटॉमिक्स ने बुधवार को एयरो इंडिया में घोषणा की कि एमक्यू-9बी गार्डिया हाई एडिट्यूड्स लॉन्ग एंड्यूरेंस (हेल) आरपीएएस को संचालित करने वाले टर्बो-प्रोपेलर इंजन को भारतीय बाजार के लिए एचएएल इंजन डिवीजन द्वारा समर्थित किया जाएगा।

RPAS - रिमोटली पाइलेटेड एयरक्राफ्ट सिस्टम्स भारत अमेरिका से सशस्त्र प्रीडेटर RPAS खरीदना चाह रहा है।

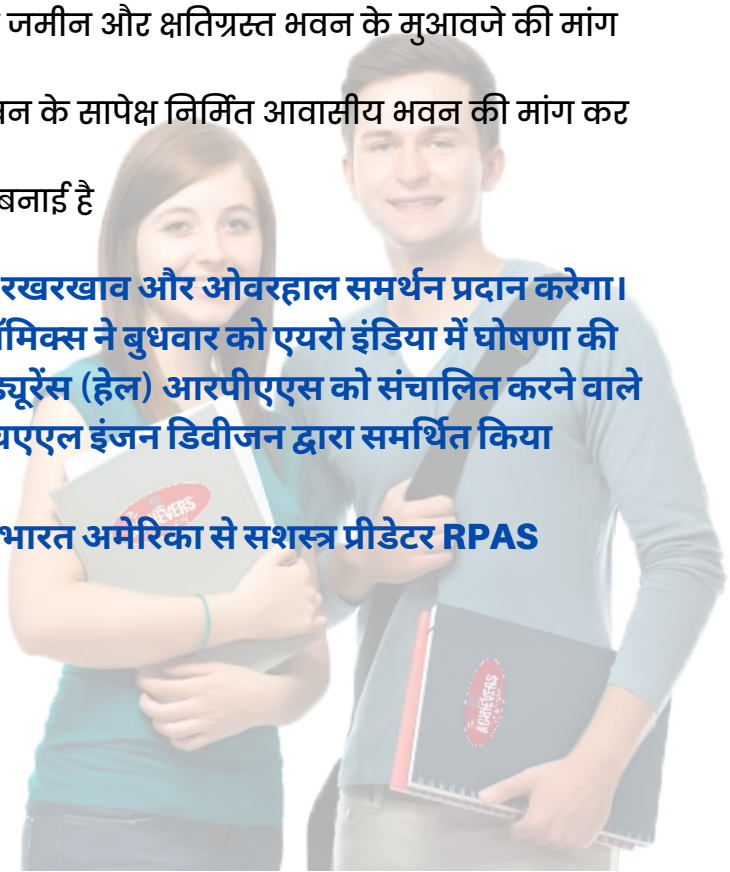

स्वदेशी कैरियर विक्रांत का संचालन साल के अंत तक किया जाएगा:

नौसेना प्रमुख
आईएनएस विक्रांत - भारत का पहला स्वदेशी विमानवाहक पोत। इसे पिछले सितंबर में नौसेना में शामिल किया गया था।
वर्तमान में आईएनएस विक्रांत एविएशन ट्रायल से गुजर रहा है, नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरि कुमार ने कहा होगा एविएशन ट्रायल- आईएनएस विक्रांत के ऊपर विमान की लैंडिंग

राज्यपाल को राजनीतिक अखाड़े में नहीं उतरना चाहिए CJI.

महाराष्ट्र के राज्यपाल ने उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली एमवीए (महाराष्ट्र विकास अघडी) सरकार को "अवसरवादी" कहा था। इस संबंध में सीजेआई डी.वाई. चंदेचुड ने कहा कि राज्यपाल को ऐसा नहीं कहना चाहिए। उन्हें राजनीतिक क्षेत्र में प्रवेश नहीं करना चाहिए।
अदालत महाराष्ट्र में राजनीतिक संकट के बाद याचिकाओं पर सुनवाई कर रही है, जिसमें वर्तमान मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने इस साल की शुरुआत में एमवीए में विद्रोह किया था।

I-T ने दूसरे दिन बीबीसी कार्यालयों का सर्वेक्षण किया

बीबीसी कार्यालय पर ओ-आई-टी सर्वेक्षण बुधवार को दूसरे दिन चला। आईटी के अधिकारी बीबीसी द्वारा किए गए लेन-देन की जांच कर रहे हैं.
इस बीच कांग्रेस ने इस तरह की कार्रवाई की आलोचना की है। पार्टी प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा, 'लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को ध्वस्त करना अब 'न्यू इंडिया' में मुंडारे की बात हो गई है.'

मर्चेंट डिस एक्सपोर्ट डिप

जनवरी में लगातार दूसरी बार भारत का निर्यात घटा है। यह 6.6% गिरकर 32-91 बिलियन हो गया। हालांकि आयात में गिरावट के कारण व्यापार घाटा 17.75 अरब तक सीमित हो गया।

त्रिपुरा में आज चुनाव हो रहे हैं।

हिन्दू 16-02-23 दुनिया

भारत के जी-20 शेरपा का कहना है कि चीन को गरीब देशों को अपने ऋणों में कटौती करनी चाहिए।

अमिताभ कांत - भारत के G20 शेरा ने बुधवार को कोलंबो में कहा कि "चीन को खुलकर सामने आने और यह कहने की जरूरत है कि उनका कर्ज क्या है और इसे कैसे चुकाना है" चीन का कर्ज चुकाओ। यह कैसे मुमकिन है कि हर किसी को बाल कटवाना पड़े."
यह भारत द्वारा चीन के लिए एक दुर्लभ और प्रत्यक्ष संदर्भ है, जबकि अमेरिका चीनी ऋण का मुखर आलोचक है। भारत शायद ही कभी इस पर टिप्पणी करता है। अतीत में भारत विकासशील देशों के लिए चीनी कर्ज को लेकर लड़ाई लड़ता रहा है।
जी 20 शेरपा का बयान महत्व रखता है क्योंकि यह हेयरकट से आगे है - इसका मतलब है कि, यह किसी विशेष ऋण खाते में बकाया राशि से कम स्वीकार करता है। एक राष्ट्र को चीन को 10,000 करोड़ वापस देने हैं लेकिन देश संकट का सामना कर रहा है।
बाल काटना

तो चीन कहता है कि 7000 करोड़ के भुगतान से ठीक हो जाएगा। तो यह 30% (10000 करोड़-7000 करोड़ =3000 करोड़) है
आईएमएफ, विश्व बैंक और भारत द्वारा 17 फरवरी को आयोजित होने वाली वैश्विक संप्रभु ऋण गोलमेज पर आभासी बैठक, जिसके बाद 25 फरवरी को व्यक्तिगत बैठक होगी।
चीनी ऋण - चीन ने लगभग 150 विकासशील देशों को 1 ट्रिलियन (1000 बिलियन) से अधिक का ऋण दिया है। कुछ एशियाई देशों जैसे पाकिस्तान, श्रीलंका, मालदीव, लाओस आदि को मिलाकर इनमें से कुछ देश जैसे श्रीलंका आर्थिक संकट का सामना कर रहे हैं और कर्ज के जाल में फंस गए हैं, जहां उन्हें अपनी जमीन चीन की सरकार को पट्टे पर देनी पड़ रही है।
BRI (बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव) के तहत ऋण दिया गया था, जो 2013 में शुरू की गई एक वैश्विक बुनियादी ढांचा विकास पहल है।

स्कॉटलैंड के नेता निकोला स्टर्जन ने इस्तीफे की घोषणा की

स्कॉटलैंड की पहली मंत्री निकोला स्टर्जन ने बुधवार को अपनी विकसित सरकार का आठ साल से अधिक समय तक नेतृत्व करने के बाद अपने इस्तीफे की घोषणा की

कम से कम 73 प्रवासियों को 'मृत मान लिया गया है' लीबिया के पास एक जहाज़ के टूटने से : संयुक्त राष्ट्र के अनुसार ।

त्रिपोली के पास कसर-ए-अखयार से यूरोप जा रहे 80 से अधिक प्रवासियों को लेकर जा रही एक नाव भूमध्य सागर में डूब गई, केवल 7 बचे पाए गए हैं 73 को मृत माना जा रहा है।

चीन का कहना है कि अमेरिकी गुब्बारे शिनजियांग, तिब्बत के ऊपर उड़े, प्रतिशोध की चेतावनी दी।

खेल

आईसीसी टी 20 महिला विश्व कप भारत बनाम वेस्टइंडीज

बंगाल बनाम सौराष्ट्र - रणजी ट्रॉफी फाइनल आज

संपादकीय

बेशर्म धमकी (Brazen Intimidation)

बीबीसी पर कर सर्वेक्षण जैसी कार्रवाइयाँ एक द्रुतशीतन प्रभाव पैदा करने के लिए होती हैं।
संपादकीय आखिर होता क्या है?
संपादकीय बीबीसी कार्यालयों में हालिया आईटी-सर्वेक्षण के बारे में बात करता है। यह उस विकास के बारे में बात करता है जिसके कारण केंद्र सरकार ने ऐसी कार्रवाई की। यह सरकार द्वारा इसी तरह की कार्रवाई के बारे में भी बात करता है। पिछले वर्षों में। साथ ही यह विश्लेषण भी करता है कि कैसे यह मीडिया की स्वतंत्रता और समग्र रूप से भारत की छवि के लिए अच्छा नहीं है

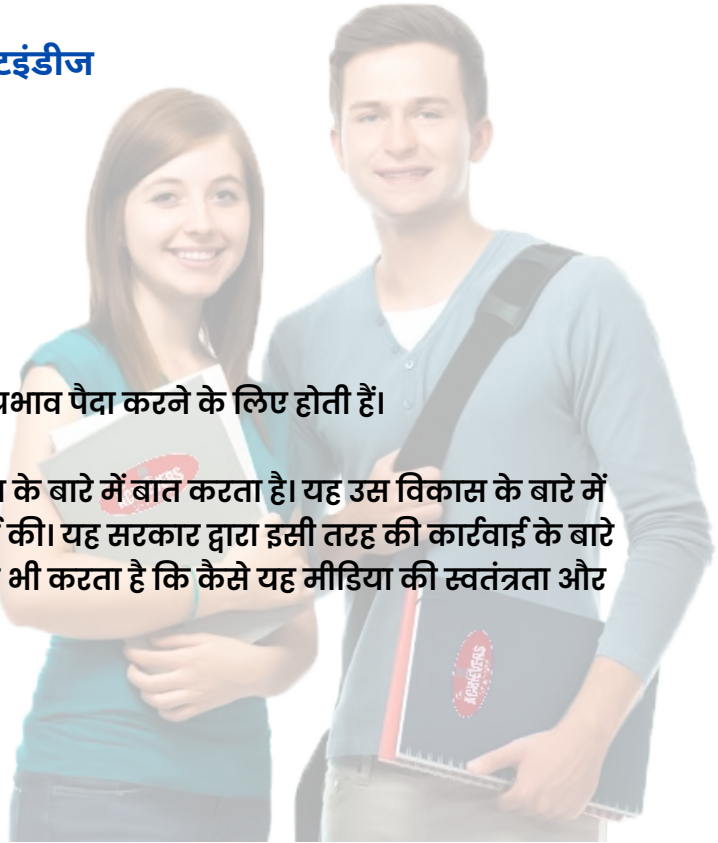

हाल के विकास क्या हैं?

आई-टी (आयकर) विभाग बीबीसी के दिल्ली और मुंबई कार्यालयों में सर्वेक्षण कर रहा है। बुधवार को दूसरे दिन सर्वे चला। अधिकारियों ने कहा कि वे "ट्रांसफर प्राइसिंग" और "मुनाफे के डायवर्जन" से संबंधित शुल्कों की तलाश कर रहे हैं, हालांकि बीबीसी की हालिया डॉक्यूमेंट्री: इंडिया: द मोदी क्वेश्चन के साथ स्पष्ट दिखाई देने वाली कड़ी को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है।

डॉक्यूमेंट्री जारी होने के बाद सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने इसे यूट्यूब सहित कई मीडिया (आईबी) प्लेटफॉर्म पर ब्लॉक कर दिया था। इनसे जुड़े ट्वीट्स भी हटा दिए गए थे। आईबी मंत्रालय ने आईटी नियम 2021 के तहत आपातकालीन शक्ति का इस्तेमाल किया। और आईटी अधिनियम, 2000 की धारा 69 ए।

अतीत में ऐसी कौन सी घटनाएं हुई हैं?

सीबीआई ने 2017 में एनडीटीवी पर छापा मारा था। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने डिजिटल पोर्टल न्यूज डिस्क पर सर्च किया था, यह दैनिक भास्कर ग्रुप पर सर्च करता है, दोनों 2021 में।

ये घटनाएं क्या दर्शाती हैं?

प्रेस की स्वतंत्रता एक फलते-फूलते लोकतंत्र का मूल है, इसका विरोध करने वाले किसी भी निकाय को हाथ से दबाने के लिए सरकार का दृष्टिकोण, भारत की छवि के साथ एक समृद्ध लोकतंत्र के रूप में अच्छा नहीं है।

संपादकीय -2

सीमाओं से परे (Beyond Limits)

जम्मू-कश्मीर में वास्तविक मुद्दे परिसीमन से अधिक राज्य का दर्जा और विशेष दर्जा हैं।

संपादकीय किस बारे में बात करता है?

संपादकीय उन मुद्दों के बारे में बात करता है जो परिसीमन के बाद जम्मू-कश्मीर में उत्पन्न हुए हैं। यह SC के हालिया निर्णय के बारे में भी बात करता है जहां इसने परिसीमन को संवैधानिक बताया था, और इसे चुनौती देने वाले अधिकारों को कम किया था।

विध्वंस के बाद जम्मू-कश्मीर के साथ क्या समस्या है

जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम के अनुसार परिसीमन अभ्यास पूरा किया गया परिसीमन में जामी क्षेत्र में छह सीटें बढ़ाई गई थीं; और कश्मीर क्षेत्र में कुल सीटों की संख्या 90 तक ले जाने वाली पार्टियां इस कवायद को मुस्लिम बहुल क्षेत्र के राजनीतिक और चुनावी महत्व को कमजोर करने का प्रयास बता रही हैं।

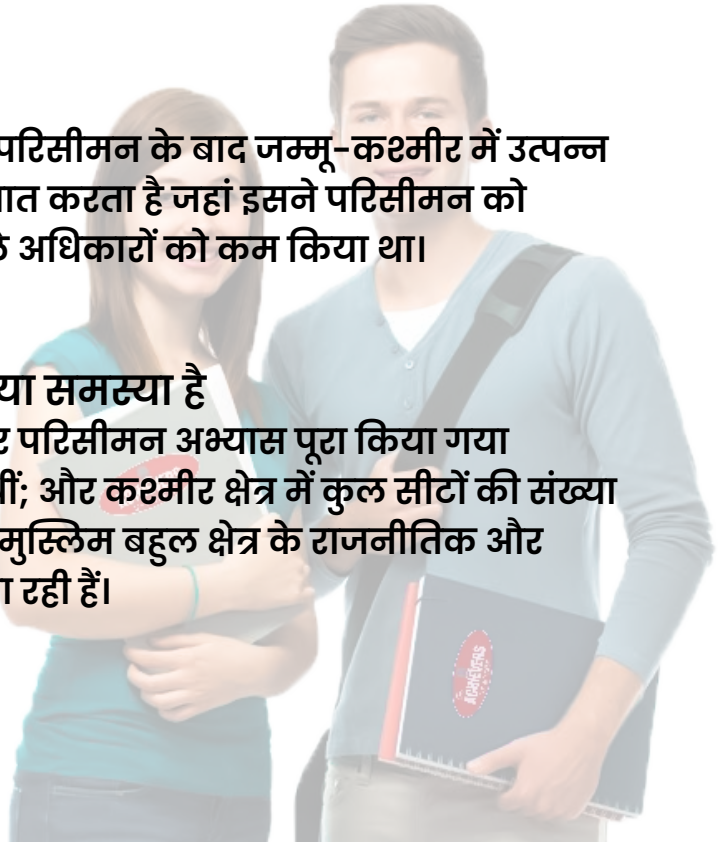

जम्मू-कश्मीर में बीजेपी के खिलाफ राजनीतिक दल इसे जम्मू-कश्मीर से उसकी स्थिति और विशेषाधिकारों को छीनने और सत्ताधारी पार्टी के लाभ के लिए राजनीति का पुनरुत्पादन करने का एक अभियान मानते हैं। उन्हें जम्मू को राजनीतिक केंद्र बनाने वाले व्यक्ति के रूप में भी देखा जाता है, कई सवालों के जवाब चुनाव होने के बाद ही मिलेंगे लेकिन वर्तमान में यह बहुत दूर लगता है।

SC का हालिया फैसला क्या था?

पूरे भारत में परिसीमन को 2026 ए/सी अनुच्छेद 170 तक रोक दिया गया है। याचिकाकर्ता बता रहा था कि परिसीमन अभ्यास असंवैधानिक है क्योंकि इस सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जम्मू-कश्मीर एक अलग मामला है और यह अपने स्वयं के पुनर्गठन कानून द्वारा शासित होगा। जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 में 2011 की जनगणना के आधार पर परिसीमन का उल्लेख किया गया है। अदालत का निर्णय सही है कि हालांकि बड़ा सवाल 2019 के तहत राज्य का दर्जा और विशेष दर्जा है।